



2026: AHC: 44537

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 726/2026

राधा कृष्णयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: बृजेश कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया और पटल पर मौजूद रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:

"1) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी करें, जो प्रतिवादी संख्या 2, चक्रवर्ती अधिकारी पडरौना, कुशीनगर को निर्देश दे कि वह उनके समक्ष लंबित यू.पी.सी.एच. अधिनियम के नियम 109 के अंतर्गत दिनांक 12.10.1989 के आवेदन को निर्धारित अवधि के भीतर तय करें।"
3. यह दलील दी गई है कि पूर्वोक्त आवेदन काफी लंबे समय से विचाराधीन है; हालांकि, इसे शीघ्रता से तय करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, और चकबंदी अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2), जिनके समक्ष पूर्वोक्त मामला निस्तारण के लिए लंबित है, को निर्देश देता है कि यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो, तो इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः चार महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार शीघ्रता से इसे तय करें।
6. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन निस्तारित किया जाता है।

फरवरी 26, 2026

विनय

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"